

अधिनियम के आधीन बिना राज्यों ने लगभग वितना गेड़ूं और चावल उपलब्ध किया है, उसका एक विवरण इस प्रकार है :

**विवरण**

राज्य	लगायत परिमाण (मनों में)
	गेड़ूं चावल
१. मध्य प्रदेश .	७,७००
२. पंजाब	८,९७,२००
३. उत्तर प्रदेश	२५,६००
४. पश्चिमी बंगाल .	२,६३,२००
५. राजस्थान	४०,६००

उत्तर प्रदेश व बिहार में अन्तर्देशी जल परिवहन सेवार्थ

\*२६८. { श्री भक्त बर्दान :  
श्री श्रीनारायण दास:

क्या परिवहन तथा संचार मंत्री १ दिसम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ४३४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश व बिहार में अन्तर्देशी जल परिवहन सेवार्थ फिर से चालू करने के बारे में इस बीच क्या प्रगति हुई है ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) : उत्तर प्रदेश और बिहार में अन्तर्देशीय जल परिवहन सर्विस को फिर से जारी करने की योजना जो सरकार के विचारधीन थी, वह आर्थिक कारणों और यातायात की मात्रा अनिश्चित होने के कारण चलने योग्य नहीं समझी गयी ।

उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच अन्तर्देशीय जल परिवहन के यातायात की मात्रा का निर्धारण करने के लिये यातायात सर्वेक्षण का इन्तजाम अग्लाइड इकनामिक रिसर्च की नेशनल काँसिल की मार्फत हाल ही में किया गया है । चार पाच महीनों में इस सर्वेक्षण के परिणामों के मिल जाने की सम्भावना है । किस प्रकार की सर्विस यहाँ आवश्यक होगी यह उन परिणामों पर ही निर्भर होगा ।

तब तक के लिये गया ब्रह्मपुत्र जल परिवहन बोर्ड ने प्रयोगात्मक रूप में दक्खर और राजमहल के बीच में साल ढोने के लिये पुनः-उत्थों द्वारा एक सर्विस चलाने का निश्चय किया है । यह सर्विस सम्भवत अगस्त, १९५९ के शुरू में चलने लगेंगी ।

**Nagarjunasagar Project**

\*299. { Shri Nagi Reddy:  
Shri D. V Rao:

Will the Minister of Irrigation and Power be pleased to state.

(a) whether the Central Water and Power Commission has considered the full project with power scheme of the Nagarjunasagar Project presented by the Government of Andhra Pradesh;

(b) if so the decisions arrived at, and

(c) what are the salient points of difference between the scheme presented by the Government of Andhra Pradesh and the decision of the Centre?

The Minister of Irrigation and Power (Hafiz Mohammad Ibrahim): (a) The Andhra and Hyderabad Governments submitted in 1954 a joint report on the Nagarjunasagar Project which covered power development also and it was decided at an inter-State conference held in February, 1955 to proceed with the present project only. No further proposals have since been received from the Andhra Pradesh Government

(b) and (c) Do not arise